

Anti-Drug Enforcement, NDPS Act, Financial Investigation



Anti-Drug Enforcement Under Operation Vajra Prahar, Baran Police has taken a significant step in curbing drug trafficking by freezing of assets worth of a little less than ₹3.92 crore that are linked to the accused drug trafficker Biramchand Lodha and his family. This action was taken under Section 68-F of the NDPS Act, which provides for the freezing of property related to narcotic offences. The operation marks a change in the way drug traffickers are arrested, from targeting them to their financial networks. In the context of the RAS exam, it is significant because it links together with the fields of internal security, Police Administration, financial investigation and anti-drug law enforcement.

Key Highlights of the Action

The movable and immovable assets of Baran Police of ₹ 3,92,81,111 were frozen.

This action was taken under the Operation 'Vajra Prahar'.

- The accused, identified as Biramchand Lodha of Dokri Khoh area of Sarathal police station, has been arrested.
- The freezing of assets also extended to his wife Phoolabai, brother Rahul Lodha and Rahul's wife Bhavana.
- The action has been approved by the competent authority in New Delhi.

- Once approved, the accused and his family are barred from using, selling and transferring the properties frozen.

Details of Frozen Assets

Immovable Property

- 2 luxurious houses were frozen.
- Also, 5 plots were subjected to freezing.

Movable Property

- A couple of cars, including Maruti and Eeco were frozen.
- One motorcycle also was frozen.
- These vehicles and properties are estimated to be valued at about ₹160,26,526/-.

Suspicious Banking Transactions

- More than the amount of ₹ 23254585 was used in a year and the amount is suspicious according to police investigation.
- These transactions did not have a valid source of income identified.
- All these financial transactions were considered part of the illegal economic network established by the drug trafficking.
- Actions are taken on the basis of the law. Actions are based on the law.

Section 68-F of the NDPS Act

- Power to freeze illegally acquired property in respect of narcotics offences is available under Section 68-F of the NDPS Act. It is applied to stop accused people from enjoying or selling such assets made from illegal drug money and/or transferring such assets.
- In this case, Sarathal Police lodged a complaint in front of the competent authority in Delhi. The authority gave its approval to the freezing order after about two months of hearing. The action was implemented according to the order dated 16 May 2026 on 2 June 2026 under the supervision of the District Collector, Baran.

Criminal Record of the Accused

- There are three serious cases against Biramchand Lodha under NDPS Act.
- One of these cases is related to the commercial quantity.
- Earlier, police had taken 250 kg of doda chura from him.
- The estimated international value of narcotic substance seized is about ₹10 lakh.
- Earlier, a car of Baleno worth of around ₹8 lakh used in trafficking was seized.

Importance for RAS Exam

Internal Security

This case demonstrates that drug trafficking is more than just law and order problem, it is also a social stability and internal security problem.

Police Administration

The operation emphasises the importance of district police, police stations, investigation units and coordination with district administration.

Financial Investigation

The action illustrates how enhanced financial monitoring is becoming more crucial to crime prevention. The police are no longer just arresting criminals, but also targeting illegal wealth.

Rule of Law

Approval by the competent authority provides a "sanction" that such action is within legal process and judicial review.

Conclusion

Baran Police's Operation Vajra Prahar to fight drug trafficking is a crucial case of economic action in the fight against drugs. The police has frozen assets worth ₹3.92 crore, sending a clear message that illegal earning of money through drugs cannot be protected. These measures help to enhance security, deter organised crime and restore the trust of the public in the police.

MCQs

MCQ 1

Baran Police's Operation Vajra Prahar primarily aimed at:

- A. Enhance the awareness of road safety issues.
- B. lock up properties associated with drug trafficking,
- C. carry out effective control of illegal mining activities
- D. investigate cases of cyber fraud

Answer: B

Baran Police had launched Operation Vajra Prahar for targeting drug traffickers and their illegal economic hold on the society. In this instance, assets estimated to be worthing of ₹3.92 crore were frozen for alleged drug trafficker Biramchand Lodha and his family under the NDPS Act.

MCQ 2

This freezing of assets was done pursuant to which provision of the NDPS Act?

- A. Section 68-F
- B. Section 144
- C. Section 302
- D. Section 124-A

Answer: A

Under Section 68-F of the NDPS Act, the properties associated with the accused drug trafficker were frozen. Under this, it is possible to freeze illegally acquired assets linked to narcotics activities and stop their use, sale or transfer.

MCQ 3

What is the meaning of this action for internal security?

- A. It only serves punishment once the individual has been found guilty.
- B. It strikes at the economic base of drug trafficking organizations.
- C. It applies only to traffic rule offences.
- D. It is an alternative to police investigation.

Answer: B

Explanation: The action is important because it is directed towards the financial basis of drug trafficking. Arrests can be used to hinder the economic activities of narcotics networks, and to help deter organised criminal activity, by freezing illegally acquired assets and suspicious bank transactions.

मादक पदार्थ नियंत्रण, एनडीपीएस अधिनियम, वित्तीय जांच

बारां पुलिस ने ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी तस्कर बिरमचन्द लोधा और उसके परिवार से जुड़ी लगभग ₹3.92 करोड़ की संपत्तियों को फ्रीज किया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत की गई, जिसके माध्यम से मादक पदार्थ अपराधों से अर्जित अवैध संपत्ति को फ्रीज किया जा सकता है। यह कार्रवाई केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके अवैध आर्थिक तंत्र को कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आरएस परीक्षा की दृष्टि से यह विषय आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासन, वित्तीय जांच और मादक पदार्थ नियंत्रण से संबंधित है।

कार्रवाई की प्रमुख विशेषताएं

- बारां पुलिस ने ₹3,92,81,111 मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को फ्रीज किया।
- यह कार्रवाई ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत की गई।
- आरोपी की पहचान सारथल थाना क्षेत्र के डोकरी खोह निवासी बिरमचन्द लोधा के रूप में हुई।
- फ्रीज की गई संपत्तियां आरोपी, उसकी पत्नी फूलाबाई, भाई राहुल लोधा और राहुल की पत्नी भावना से जुड़ी हैं।
- कार्रवाई को नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी से विधिक मंजूरी मिली।
- मंजूरी के बाद आरोपी और उसका परिवार इन संपत्तियों का उपयोग, विक्रय या हस्तांतरण नहीं कर सकेगा।

फ्रीज की गई संपत्तियों का विवरण

अचल संपत्ति

- 2 आलीशान मकान फ्रीज किए गए।
- 5 प्लॉट भी फ्रीजिंग कार्रवाई के दायरे में लाए गए।

चल संपत्ति

- 2 कारें, जिनमें मारुति और ईको शामिल हैं, फ्रीज की गईं।
- 1 मोटरसाइकिल भी फ्रीज की गई।
- इन वाहनों और संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग ₹1,60,26,526 है।

संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन

- पुलिस जांच में एक वर्ष में ₹2,32,54,585 के संदिग्ध लेनदेन का पता चला।
- इन लेनदेन का कोई वैध आय स्रोत नहीं मिला।
- इन वित्तीय लेनदेन को मादक पदार्थ तस्करी से बने अवैध आर्थिक तंत्र का हिस्सा माना गया।

कार्रवाई का विधिक आधार

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ मादक पदार्थ अपराधों से जुड़ी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को फ्रीज करने की शक्ति प्रदान करती है। इसका उद्देश्य आरोपी व्यक्तियों को अवैध नशा कारोबार से बनाई गई संपत्ति का उपयोग, विक्रय या हस्तांतरण करने से रोकना है।

इस मामले में सारथल पुलिस ने नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। लगभग दो महीने की सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी ने फ्रीजिंग आदेश को मंजूरी दी। 16 मई 2026 के आदेश के अनुपालन में 2 जून 2026 को जिला कलेक्टर बारां के निर्देश पर कार्रवाई संपादित की गई।

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड

- बिरमचन्द लोधा के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत 3 गंभीर मामले दर्ज हैं।
- इनमें से 1 मामला वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है।
- पुलिस पूर्व में उसके कब्जे से 250 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त कर चुकी है।
- जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग ₹10 लाख है।
- तस्करी में प्रयुक्त लगभग ₹8 लाख कीमत की बलेनो कार भी पूर्व में जब्त की जा चुकी है।

आरएस परीक्षा की दृष्टि से महत्त्व

आंतरिक सुरक्षा

यह मामला दर्शाता है कि मादक पदार्थ तस्करी केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है।

पुलिस प्रशासन

इस कार्रवाई से जिला पुलिस, थाना स्तर की जांच, विशेष टीमों और जिला प्रशासन के समन्वय की भूमिका स्पष्ट होती है।

वित्तीय जांच

यह कार्रवाई दिखाती है कि अपराध नियंत्रण में वित्तीय निगरानी का महत्त्व बढ़ रहा है। पुलिस अब केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अवैध संपत्ति और आर्थिक नेटवर्क को भी निशाना बना रही है।

विधि का शासन

सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी यह सुनिश्चित करती है कि ऐसी कार्रवाई विधिक प्रक्रिया और न्यायिक परीक्षण के अनुरूप हो।

निष्कर्ष

बारां पुलिस का ऑपरेशन वज्र प्रहार मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ₹3.92 करोड़ की संपत्ति फ्रीज करके पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति सुरक्षित नहीं रह सकती। ऐसी कार्रवाइयां आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करती हैं, संगठित अपराध को हतोत्साहित करती हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाती हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1

बारां पुलिस के ऑपरेशन वज्र प्रहार का मुख्य उद्देश्य क्या था?

- A. सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना
- B. मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ी संपत्तियों को फ्रीज करना

- C. अवैध खनन गतिविधियों को नियंत्रित करना
D. साइबर अपराध मामलों की जांच करना

उत्तर: B

व्याख्या: ऑपरेशन वज्र प्रहार बारां पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों और उनके अवैध आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए चलाया गया। इस मामले में आरोपी तस्कर बिरमचन्द लोधा और उसके परिवार से जुड़ी लगभग ₹3.92 करोड़ की संपत्तियां एनडीपीएस अधिनियम के तहत फ्रीज की गईं।

प्रश्न 2

इस मामले में संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की किस धारा के तहत की गई?

- A. धारा 68-एफ
B. धारा 144
C. धारा 302
D. धारा 124-ए

उत्तर: A

व्याख्या: आरोपी तस्कर से जुड़ी संपत्तियां एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत फ्रीज की गईं। यह धारा मादक पदार्थ अपराधों से जुड़ी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को फ्रीज करने और उसके उपयोग, विक्रय या हस्तांतरण को रोकने की अनुमति देती है।

प्रश्न 3

आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से इस कार्रवाई का सबसे उपयुक्त महत्त्व क्या है?

- A. यह केवल दोष सिद्ध होने के बाद दंड देने पर केंद्रित है।
B. यह मादक पदार्थ तस्करी संगठनों की आर्थिक नींव पर प्रहार करती है।
C. यह केवल यातायात नियम उल्लंघन से संबंधित है।
D. यह पुलिस जांच की आवश्यकता को समाप्त कर देती है।

उत्तर: B

व्याख्या: यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मादक पदार्थ तस्करी की आर्थिक नींव को निशाना बनाती है। अवैध संपत्तियों और संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन को फ्रीज करके पुलिस नशा तस्करी नेटवर्क की आर्थिक शक्ति को कमजोर कर सकती है और संगठित अपराध को हतोत्साहित कर सकती है।

Ayushman Bharat Digital Mission, ABHA ID, Digital Health Infrastructure



In 2026, India will reach a milestone of 90 crore ABHA accounts with Ayushman Bharat Digital Mission. Rajasthan has crossed a significant milestone and is in second place in the country with the creation of over 7.19 crore of ABHA IDs. ABHA, or Ayushman Bharat Health Account, is a special digital health identity, which enables citizens to store, access and share their health data with their consent. The development is significant for the RAS exam as it links the aspects of health governance with digital public infrastructure, citizen-centric service delivery and technology application in public administration.

Key Highlights

- In 2026, India achieved the milestone of 90 crore ABHA accounts.
- ABHA ID was issued by more than 7.19 crore by Rajasthan.
- Rajasthan ranked second in the country regarding creation of ABHA account.
- ABHA enables citizens to conveniently handle their health details digitally.
- The system supports citizens to have transparency on the delivery of health services.
- Patients are able to access their medical details via their mobile devices with digital platforms.
- The initiative is a part of the Ayushman Bharat Digital Mission.

Growth of ABHA Accounts in India

The number of ABHA accounts has been steadily growing over the past 5 years.

- 2021: 14.7 crore accounts
- 2022: 30.4 crore accounts
- 2023: 50.6 crore accounts
- 2024: 72.2 crore accounts
- 2025: 84.5 crore accounts

At 2026, there are over 90 crore accounts.

This growth reflects how fast India's digital health space is expanding and how much acceptance digital health identity has garnered amongst citizens.

What is ABHA?

Ayushman Bharat Health Account is the code name of ABHA. Citizens have a unique digital health identity to secure them to link, view and share with their permission the health information they possess. It assists to build up a comprehensive digital health history between hospitals, labs, doctors and health applications.

In this framework, each registered citizen will receive a health ID that is unique to them and has a total of 14 numbers. This ID serves as the foundation for digitally holding medical history, laboratory reports, prescriptions and disease-related information.

Benefits of ABHA for Citizens

You can easily access your health records.

Under ABHA, citizens can store their health records electronically. This decreases the need to bring physical medical records with you to healthcare facilities or doctors.

Better Treatment

Linked digital records enable doctors to more deeply understand the medical history of a patient. This aids to prompt and proper treatment.

Consent-Based Data Sharing

A patient's digital health record is only accessible by their doctor, hospital or health institution upon the patient's consent. This enhances privacy and data security.

Continuity of Care

Medical history and lab report and prescription information are digitally connected, thus enabling patients to get a better continuity of care from various health establishments.

Role of Ayushman Bharat Digital Mission

The Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) facilitates a digital platform that will allow patients, doctors, hospitals and health service providers to connect with one another. It is missioned to create a robust digital health ecosystem in India.

ABHA is an integral part of this mission. It facilitates secure connectivity of EHRs and enhanced inter-professional collaboration.

Role of IHMS

IHMS is an important player in this digital health innovation. It is an ABDM compliant software for the linkage of the electronic health records with ABHA ID of the patients. This enables hospitals to keep their health records digitally, structured and accessible.

Importance for RAS Exam

Health Governance

The effort illustrates the possibilities of leveraging technology to enhance the delivery of public health services and make health care more accessible.

Digital Public Infrastructure

Just like digital identification and digital payments, ABHA is an example of digital public infrastructure in the health domain.

Citizen-Centric Administration

The system helps to provide citizens with more control over their health information and increases transparency in health service provision.

The protection of personal data and consent.

It is necessary to understand the balance between digital governance and individual privacy through the consent-modelled sharing.

Conclusion

The launch of over 90 crore ABHA accounts under Ayushman Bharat Digital Mission is a significant milestone towards digitalizing India's healthcare system. Despite being a state in the midst of transitioning towards digital healthcare, Rajasthan has achieved a high rank of over 7.19 crore ABHA IDs in India, which is due to good implementation at the state level. This will enhance transparent, secure and citizen-centric healthcare delivery.

MCQs

MCQ 1

Which is the primary objective of Ayushman Bharat Digital Mission (ABHA)?

- A. To enable citizens to access online services.C. To be able to access online services.
- B. To use private hospitals instead of public ones.D. To have public hospitals replaced by private ones.
- C. To allow for public access to medicines in rural areas.E. To ensure public access to medicines in rural areas at no cost.
- D. To monitor admission in medical colleges

Answer: A

Explanation: Ayushman Bharat Health Account (ABHA) is a digital health identity given to the citizens. It gives them the ability to securely link, view and share their health records with consent. It helps in creating a digital health ecosystem by connecting patients, doctors, hospitals and health applications.

MCQ 2

How many ABHA ID's does Rajasthan have on the basis of this information?

- A. More than 900 crores
- B. More than 14.7 crore
- C. More than 7.19 crore
- D. More than 84.5 crore

Answer: C

Explanation: Rajasthan has issued over 7.19 crore ABHA IDs and ranked itself 2nd in the country. The milestone is a testament to the state's progress in digital health initiatives and implementing the Ayushman Bharat Digital Mission.

MCQ 3

Which of the following is the most accurate statement about the feature of "consent" in ABHA?

- A. All records are available to doctors without the consent of patients.
- B. The ABHA record is not available with any other hospital except government hospitals.
- C. Health records of patients can be accessed by patients only.
- D. ABHA records are only used for insurance claims.

Answer: C

Explanation: ABHA works on a consent-based data-sharing model. Any doctor or hospital cannot access a patient's medical history, prescriptions, lab reports or other digital health records without the patient's consent. This is an enhancement of privacy, transparency and citizens' control of health information.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आभा पहचान, अंकीय स्वास्थ्य संरचना

भारत ने वर्ष 2026 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 90 करोड़ आभा खातों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। राजस्थान ने 7.19 करोड़ से अधिक आभा पहचान बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आभा अर्थात आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नागरिकों को एक विशिष्ट अंकीय स्वास्थ्य पहचान प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वे अपनी सहमति से स्वास्थ्य अभिलेखों को सुरक्षित रूप से जोड़, देख और साझा कर सकते हैं। आरएएस परीक्षा की दृष्टि से यह विषय स्वास्थ्य शासन, अंकीय लोक संरचना, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण और लोक प्रशासन में तकनीक के उपयोग से संबंधित है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2026 में भारत ने 90 करोड़ आभा खातों का आंकड़ा पार किया।
- राजस्थान ने 7.19 करोड़ से अधिक आभा पहचान बनाई।
- आभा खाते बनाने में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा।
- आभा नागरिकों को अपने स्वास्थ्य अभिलेख अंकीय रूप में प्रबंधित करने की सुविधा देता है।
- यह व्यवस्था पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करती है।
- मरीज अपने स्वास्थ्य अभिलेख मोबाइल आधारित अंकीय माध्यमों से देख सकते हैं।

- यह पहल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा है।

भारत में आभा खातों की वृद्धि

पिछले 5 वर्षों में आभा खातों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

- 2021: 14.7 करोड़ खाते
- 2022: 30.4 करोड़ खाते
- 2023: 50.6 करोड़ खाते
- 2024: 72.2 करोड़ खाते
- 2025: 84.5 करोड़ खाते
- 2026: 90 करोड़ से अधिक खाते

यह वृद्धि भारत के अंकीय स्वास्थ्य तंत्र के तेज विस्तार और नागरिकों के बीच अंकीय स्वास्थ्य पहचान की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है।

आभा क्या है?

आभा का पूरा नाम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है। यह नागरिकों को एक विशिष्ट अंकीय स्वास्थ्य पहचान प्रदान करता है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी सहमति से स्वास्थ्य अभिलेखों को सुरक्षित रूप से जोड़, देख और साझा कर सकते हैं। यह अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सकों और स्वास्थ्य अनुप्रयोगों के बीच दीर्घकालिक अंकीय स्वास्थ्य अभिलेख तैयार करने में सहायक है।

इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक पंजीकृत नागरिक को 14 अंकों की विशिष्ट आभा स्वास्थ्य पहचान मिलती है। यही पहचान चिकित्सा इतिहास, जांच प्रतिवेदन, औषधि पर्चे और रोग संबंधी जानकारी को अंकीय रूप में सुरक्षित रखने का आधार बनती है।

नागरिकों के लिए आभा के लाभ

स्वास्थ्य अभिलेखों तक आसान पहुंच

आभा नागरिकों को अपने स्वास्थ्य अभिलेख अंकीय रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देता है। इससे अस्पताल या चिकित्सक के पास जाते समय कागजी दस्तावेज साथ ले जाने की आवश्यकता कम हो जाती है।

बेहतर उपचार

जुड़े हुए अंकीय अभिलेखों के माध्यम से चिकित्सक मरीज के पुराने चिकित्सा इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे समय पर और सही उपचार उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है।

सहमति आधारित जानकारी साझा करना

मरीज की अनुमति के बिना कोई भी चिकित्सक, अस्पताल या स्वास्थ्य संस्था उसके अंकीय स्वास्थ्य अभिलेख नहीं देख सकती। इससे निजता और जानकारी की सुरक्षा मजबूत होती है।

उपचार की निरंतरता

चिकित्सा इतिहास, जांच प्रतिवेदन और औषधि पर्चे अंकीय रूप से जुड़े होने के कारण मरीजों को विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर और निरंतर उपचार मिल सकता है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की भूमिका

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसा अंकीय मंच उपलब्ध कराता है, जहां मरीज, चिकित्सक, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपस में जुड़ सकते हैं। इसका उद्देश्य भारत में मजबूत अंकीय स्वास्थ्य तंत्र का निर्माण करना है।

आभा इस मिशन के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है। यह इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेखों को सुरक्षित रूप से जोड़ने और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देता है।

आईएचएमएस की भूमिका

आईएचएमएस इस अंकीय स्वास्थ्य नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप एक अनुप्रयोग प्रणाली है, जिसके माध्यम से मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख उनकी आभा पहचान से जोड़े जाते हैं। इससे अस्पताल स्वास्थ्य जानकारी को सुव्यवस्थित और सुलभ अंकीय रूप में संधारित कर सकते हैं।

आरएस परीक्षा की दृष्टि से महत्त्व

स्वास्थ्य शासन

यह पहल दिखाती है कि तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा सकता है।

अंकीय लोक संरचना

आभा स्वास्थ्य क्षेत्र में अंकीय लोक संरचना का उदाहरण है, जैसे अंकीय पहचान और अंकीय भुगतान प्रणालियां अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नागरिक-केंद्रित प्रशासन

यह व्यवस्था नागरिकों को अपने स्वास्थ्य अभिलेखों पर अधिक नियंत्रण देती है और स्वास्थ्य सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाती है।

जानकारी की निजता और सहमति

सहमति आधारित जानकारी साझा करने की व्यवस्था अंकीय शासन और व्यक्तिगत निजता के बीच संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 90 करोड़ से अधिक आभा खातों का निर्माण भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अंकीय परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम है। राजस्थान द्वारा 7.19 करोड़ से अधिक आभा पहचान बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त करना राज्य स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है। यह पहल पारदर्शी, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A. नागरिकों को अंकीय स्वास्थ्य पहचान प्रदान करना
- B. सभी निजी अस्पतालों को बंद करना
- C. केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त औषधियां उपलब्ध कराना
- D. चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश को नियंत्रित करना

उत्तर: A

व्याख्या: आभा अर्थात आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नागरिकों को एक विशिष्ट अंकीय स्वास्थ्य पहचान प्रदान करता है। इसके माध्यम से वे अपनी सहमति से स्वास्थ्य अभिलेखों को सुरक्षित रूप से जोड़, देख और साझा कर सकते हैं। यह मरीजों, चिकित्सकों, अस्पतालों और स्वास्थ्य अनुप्रयोगों को जोड़कर अंकीय स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करता है।

प्रश्न 2

दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान ने कितनी आभा पहचान बनाई हैं?

- A. 90 करोड़ से अधिक
- B. 14.7 करोड़ से अधिक
- C. 7.19 करोड़ से अधिक
- D. 84.5 करोड़ से अधिक

उत्तर: C

व्याख्या: राजस्थान ने 7.19 करोड़ से अधिक आभा पहचान बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों तक अंकीय स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में राज्य की प्रगति को दर्शाती है।

प्रश्न 3

आभा की सहमति आधारित विशेषता को सबसे सही रूप में कौन सा कथन बताता है?

- A. चिकित्सक मरीज की अनुमति के बिना सभी अभिलेख देख सकते हैं।
- B. केवल सरकारी अस्पताल आभा अभिलेख देख सकते हैं।
- C. मरीज के स्वास्थ्य अभिलेख उसकी सहमति से ही देखे जा सकते हैं।
- D. आभा अभिलेख केवल बीमा दावों के लिए उपयोग होते हैं।

उत्तर: C

व्याख्या: आभा सहमति आधारित जानकारी साझा करने की व्यवस्था पर कार्य करता है। मरीज की अनुमति के बिना कोई भी चिकित्सक या अस्पताल उसकी चिकित्सा जानकारी, जांच प्रतिवेदन, औषधि पर्चे या अन्य अंकीय स्वास्थ्य अभिलेख नहीं देख सकता। यह व्यवस्था निजता, पारदर्शिता और स्वास्थ्य जानकारी पर नागरिक के नियंत्रण को मजबूत करती है।

Water Conservation, ERCP, Irrigation Management, Public Participation



Water Conservation: Vande Ganga Jal Sanrakshan Jan Abhiyan organised a water conservation and awareness creation programme in Kalakho Dam, Dausa district. This was accompanied by the worship of water, Kalash Yatra, plantation activities and community participation. Water Resources Minister Suresh Singh Rawat emphasized the need for conserving water and people's participation in the protection of water resources. He further said that the Eastern Rajasthan Canal Project will boost the irrigation facilities in Dausa and other areas of eastern Rajasthan. This topic is important for RAS exam because it is related to water resource management, environmental conservation, public participation and irrigation development in Rajasthan.

Key Highlights

The programme was conducted at Kalakho Dam of Dausa district.

Water worship, Kalash Yatra and plantation activities were done.

Water Resources Minister Suresh Singh Rawat was in attendance at the event.

Water Conservation & Environmental Protection were among the themes thrust through the campaign.

There were many women, village residents, public representatives and officials as well as social workers.

The minister highlighted the need of maximum rain water harvesting and conservation of traditional water sources.

Pre-rainy season instructions were provided for water source repair and canals/anicut repair.

Importance of Vande Ganga Jal Sanrakshan Jan Abhiyan

The objective of Vande Ganga Jal Sanrakshan Jan Abhiyan is to spread awareness among the public regarding water conservation, protection of water bodies, environmental responsibility etc. The campaign includes water worship, plantation mobilisation and community mobilisation to make water conservation a people's movement.

The campaign is particularly important for the state of Rajasthan as it is an area with issues of water scarcity and inadequate rainfall, relying on irrigation infrastructure. There is a potential for public participation to assist with conserving rainwater, maintaining local water bodies and alleviating the pressure on ground water.

ERCP is a crucial procedure in Eastern Rajasthan.

Strengthening Irrigation

It is expected that the water availability will be enhanced in Dausa and other areas of eastern Rajasthan through Eastern Rajasthan Canal Project. This is the project to transfer water from rivers like Kalisindh, Chambal, Parvati to water stressed areas.

Benefits for Farmers

The minister has declared that farmers will benefit from ERCP, as it will supply them with sufficient water for irrigation. Enhanced water supplies can be used to improve the productivity of agriculture and alleviate uncertainty arising from the dependence on rain.

Regional Water Security

The importance of ERCP in eastern Rajasthan is that it can enhance the water security in the long-term, better irrigation system and support the livelihood of the rural population.

Assignments for Canal and Water Source Management

Minister of State for Water Resources Suresh Singh Rawat asked for proper repairs to water sources, canals and anicuts ahead of the monsoon rains. He also gave directions for making a restoration of the old canal system and for removing encroachments on the canals and water routes.

These directions are crucial as they contribute to minimizing the loss of water, enhancing water flow and providing farmers with timely irrigation assistance through proper maintenance of irrigation infrastructure.

A voice for the environment: through the plantation.

During the programme, plantation activities were also conducted to encourage the protection of the environment. On World Environment Day 5 June the minister called for maximum planting. He emphasized the need of water conservation and environmental conservation should be pushed as a mass movement.

Plantation contributes to the betterment of soil moisture, erosion control and balance of ecological factors. Plantation activities are strongly associated with long-term water and environmental sustainability in a state such as Rajasthan.

Importance for RAS Exam

Water Conservation

The campaign focuses on the need of rainwater harvesting and water body protection and community involvement in water management.

Irrigation Development

ERCP is relevant to irrigation expansion and water distribution and agricultural development in eastern Rajasthan region.

Environmental Governance

This programme illustrates the part played by the government, local administration and **citizens in the promotion of environmental awareness.**

Public Participation

Jan Bhagidari is seen in Kalash Yatra, plantation and public awareness activities, which are all significant in the success of conservation campaign.

Conclusion

Vande Ganga Jal Sanrakshan Jan Abhiyan at Kalakho Dam made a powerful message on water conservation and environmental protection. The emphasis on ERCP, repair of canals, removal of encroachments and plantation is a general trend in water resource management. These campaigns are crucial for Rajasthan, where the goal of ensuring irrigation security will be met, sustainable water use and community-led environmental protection will be promoted.

MCQs

MCQ 1

Where was the water conservation programme under Vande Ganga Jal Sanrakshan Jan Abhiyan organised in Dausa district?

- A. Bisalpur Dam
- B. Kalakho Dam
- C. Mahi Dam
- D. Jawai Dam

Answer: B

Explanation: Vande Ganga Jal Sanrakshan Jan Abhiyan was held at Kalakho dam in Dausa district. The event featured the water worship, Kalash Yatra, plantation and public awareness program to disseminate the message of water conservation and protection of the environment.

MCQ 2

Which project was emphasised as a key water supply project in Dausa and the eastern part of Rajasthan for improving the irrigation capacity?

- A. Eastern Rajasthan Canal Project
- B. Indira Gandhi Canal Project
- C. Narmada Canal Project
- D. Chambal Command Area Project

Answer: A

Water Resources Minister Suresh Singh Rawat showcased the role being played by the Eastern Rajasthan Canal Project in enhancing water availability in Dausa and other areas of eastern Rajasthan. The said project is likely to provide water to rivers like Kalisindh, Chambal and Parvati and benefit the farmers by providing irrigation facilities.

MCQ 3

In the programme what did they do to encourage environmental protection?

- A. Plantation
- B. Industrial survey
- C. Mining auction
- A. Traffic awareness campaign

Answer: A

Plantation was carried out as a part of the programme in the message of environmental protection. Plantation was another activity that linked water conservation with ecological sustainability, along with water worship and Kalash Yatra. The minister has also appealed for maximum plantation on the occasion of World Environment Day, 5 June.

जल संरक्षण, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, सिंचाई प्रबंधन, जनभागीदारी

दौसा जिले के कालाखो बांध पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण एवं जन-जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल पूजन, कलश यात्रा, पौधारोपण और सामुदायिक भागीदारी जैसी गतिविधियां हुईं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जल स्रोतों के संरक्षण और जनभागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से दौसा और पूर्वी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी। आरएएस परीक्षा की दृष्टि से यह विषय राजस्थान में जल संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जनभागीदारी और सिंचाई विकास से संबंधित है।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम दौसा जिले के कालाखो बांध पर आयोजित किया गया।
- जल पूजन, कलश यात्रा और पौधारोपण की गतिविधियां आयोजित हुईं।
- जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
- अभियान के माध्यम से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
- महिलाओं, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
- मंत्री ने वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
- वर्षा ऋतु से पहले जल स्रोतों, नहरों और एनीकटों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का महत्व

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, जल निकायों की सुरक्षा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना है। जल पूजन, पौधारोपण और सामुदायिक सहभागिता जैसी गतिविधियों के माध्यम से यह अभियान जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास करता है।

राजस्थान जैसे राज्य के लिए यह अभियान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां जल scarcity, असमान वर्षा और सिंचाई तंत्र पर निर्भरता जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। जनभागीदारी के माध्यम से वर्षा जल का संरक्षण, स्थानीय जल स्रोतों का रखरखाव और भूजल पर दबाव कम करने में सहायता मिल सकती है।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की भूमिका

सिंचाई व्यवस्था को मजबूती

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से दौसा और पूर्वी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ने की संभावना है। इस परियोजना के माध्यम से कालीसिंध, चंबल और पार्वती जैसी नदियों का जल जल-अभाव वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

किसानों को लाभ

मंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में सहायक होगी। जल उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है और वर्षा पर निर्भरता से जुड़ी अनिश्चितता कम हो सकती है।

क्षेत्रीय जल सुरक्षा

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दीर्घकालिक जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई तंत्र और ग्रामीण आजीविका को मजबूती प्रदान कर सकती है।

नहर और जल स्रोत प्रबंधन के निर्देश

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अधिकारियों को वर्षा ऋतु से पहले जल स्रोतों, नहरों और एनीकटों की आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुरानी केनाल प्रणाली की मरम्मत कराने और नहरों एवं जल मार्गों पर हुए अतिक्रमण हटाने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।

ये निर्देश महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सिंचाई ढांचे के उचित रखरखाव से जल हानि कम होती है, जल प्रवाह बेहतर होता है और किसानों को समय पर सिंचाई सहायता मिलती है।

पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण का संदेश

कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण भी किया गया। मंत्री ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया। उन्होंने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता बताई।

पौधारोपण से मिट्टी की नमी बढ़ाने, कटाव कम करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। राजस्थान जैसे राज्य में पौधारोपण गतिविधियां दीर्घकालिक जल और पर्यावरणीय स्थिरता से गहराई से जुड़ी हैं।

आरएस परीक्षा की दृष्टि से महत्व

जल संरक्षण

यह अभियान वर्षा जल संचयन, जल निकायों की सुरक्षा और जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को स्पष्ट करता है।

सिंचाई विकास

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पूर्वी राजस्थान में सिंचाई विस्तार, क्षेत्रीय जल वितरण और कृषि विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

पर्यावरणीय शासन

यह कार्यक्रम सरकार, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों की पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में भूमिका को दर्शाता है।

जनभागीदारी

कलश यात्रा, पौधारोपण और जन-जागरण गतिविधियां संरक्षण अभियानों की सफलता में जनभागीदारी के महत्त्व को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष

कालाखो बांध पर आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश दिया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, नहरों की मरम्मत, अतिक्रमण हटाने और पौधारोपण पर जोर जल संसाधन प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। राजस्थान के लिए ऐसे अभियान सिंचाई सुरक्षा, सतत जल उपयोग और समुदाय आधारित पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1

दौसा जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया?

- A. बीसलपुर बांध
- B. कालाखो बांध
- C. माही बांध
- D. जवाई बांध

उत्तर: B

व्याख्या: वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम दौसा जिले के कालाखो बांध पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल पूजन, कलश यात्रा, पौधारोपण और जन-जागरण गतिविधियां आयोजित हुईं, जिनके माध्यम से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

प्रश्न 2

दौसा और पूर्वी राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस परियोजना को महत्वपूर्ण बताया गया?

- A. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
- B. इंदिरा गांधी नहर परियोजना
- C. नर्मदा नहर परियोजना
- D. चंबल कमांड क्षेत्र परियोजना

उत्तर: A

व्याख्या: जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस परियोजना से दौसा और पूर्वी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ने की संभावना है। कालीसिंध, चंबल और पार्वती नदियों का जल क्षेत्र तक पहुंचने से किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सकती है।

प्रश्न 3

कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी गतिविधि आयोजित की गई?

- A. पौधारोपण
- B. औद्योगिक सर्वेक्षण
- C. खनन नीलामी
- D. यातायात जागरूकता रैली

उत्तर: A

व्याख्या: कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पौधारोपण किया गया। जल पूजन और कलश यात्रा के साथ पौधारोपण ने जल संरक्षण को पारिस्थितिक स्थिरता से जोड़ा। मंत्री ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर अधिक से अधिक पौधारोपण करने का भी आह्वान किया।